भारत में शहरीकरण और विकास की प्रक्रिया

डॉ0 ओम प्रकाश सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य
हरिशचन्द्र स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

आजादी के बाद भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। अंग्रज शासकों ने भारत को उपनिवेश बना कर इसकी विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध कर रखा था। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के शहर एवं उसके नजदीक क्षेत्र उनकी रणनीति के अनुकूल थे। फलतः विकास भी कुछ खास क्षेत्रों तक सिमटा रहा।

भारत द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रारुप को अंगीकार करने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ा। फलतः सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक विशाल उपक्रमों की स्थापना हुई। जिन स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने स्थापित हुए वे कालान्तर में शहर के रुप में रुपान्तरित होते गये। राउर केला, बोकारों, मिलाई, अनपरा, ओबरा, शक्ति नगर इसके प्रतीक हैं।

1901 की जनगणना के अनुरुप भारत में शहरी आबादी मात्र 11.4 प्रतिशत थी जबकि 2001 में यह 28.53 प्रतिशत हो गयी। 2011 की जनगणना के आकड़ों के अनुसार यह 31.16 प्रतिशत शहरी आबादी थी, जिसके 2030 तक भारत की कुल जनसंख्या का 40.76 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। शहरीकरण को तेज गति को यह तथ्य भी इंगित करता है कि भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की कुल संख्या 277 है।

भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि शहरों के ढांचे में स्थिरता रही है, अर्थात् शहरी आबादी चार गुना बढ़ने के उपरान्त भी शहरों की संख्या केवल डेढ़ गुनी ही बढ़ी। इसका अर्थ यह है कि विद्यमान शहरों में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ी है।, इसकी तुलना में नये शहरों को विकास ज्यादा नहीं हुआ है। पुराने गांव जो शहर में बदले उनकी भी संख्या बहुत अधिक नहीं है। यह सब शहरी ढांचे में स्थिरता का प्रमाण है और इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में सामाजिक आर्थिक ढांचे में बदलाव आसान नहीं है। देखने में आता है कि अधिकांश गांवों की जनसंख्या लम्बे समय से स्थिर है। छोटे कस्बे जिनका आकार भी लगभग स्थिर है। गावों के लिए बाजार और सेवा केन्द्रों का काम करते है। हर क्षेत्र एवं उपक्षेत्र में विभिन्न वर्गों में आने वाले शहर भी प्रायः स्थिर है और ऐसा लगता है कि शहरों के इन वर्गों में भी दीर्घकालिक स्थिरता बनी हुई है और शहरी विकास का रुप यह रहा है कि विद्यमान शहरों की जनसंख्या बढ़ती गयी है अरौर नये शहरों का विकास ज्यादा नहीं हुआ। वस्तुतः शहरीकरण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रतिफल है। कृषि का व्यापारीकरण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, यातायात एवं संचार साधनों का विकास लोकनीति, शासकीय निर्णय, जनसंख्या वृद्धि दर तथा प्रवास की गति आदि शहरीकरण के प्रेरक तत्व माने जाते है।

शहरीकरण समाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का परिणाम हैं जो मूल रुप में औद्योगीकरण के स्तर से प्रभावित होता है, जिन राज्यों में उच्च औद्योगीकरण की दर है वहां शहरीकरण की गति भी तेज है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु। इन तीनों राज्यों में भारत की कुल शहरी जनसंख्या का 34 प्रतिशत निवास करती है। यद्यपि विभिन्न प्रदेशों में शहरीकरण की प्रक्रिया में विषमता व्याप्त है, लेकिन सम्पूर्ण देश उच्च शहरीकरण एवं आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है। फिर भी निरपेक्ष रुप से भारत में शहरीकरण का वर्तमान स्तर (लगभग 31.16 प्रतिशत शहरी आबादी) सम्पूर्ण विश्व के शहरीकरण की तुलना में बहुत कम है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड अरबनाईजेशन प्रास्पेक्टस (2014) रिपोर्ट के अनुसार 2014 में सम्पूर्ण विश्व की लगभग 54 प्रतिशत जनंसख्या शहरों में निवास करती है। वर्तमान समय में उत्तर अमेरिका की लगभग 82 प्रतिशत आबादी शहरी है, लेकिन अमेरिका एवं कैरेबियन द्वीप की 80 प्रतिशत जनता शहरों में निवास करती है। अफ्रीका में 40 प्रतिशत तथा एशिया में 48 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है।

इस प्रकार भारत का शहरीकरण स्तर पुरे विश्व के औसत शहरीकरण के औसत से नीचा है। किसी भी देश में शहरीकरण उस देश की अवस्थापना सुविधाओं के विस्ताार पर निर्भर करता है। जिन देशों में अवस्थापना सुविधायें अधिक विकसित है, वहां शहरीकरण भी अधिक है, जैसे अमेरिका, जापान, सिंगापुर, कनाडा आदि देशों का नगरीकरण स्तर लगभग 80 से 70 प्रतिशत है।

शहरीकरण एवं आर्थिक विकास :–

शहरीकरण आर्थिक विकास से घनिष्ठ रुप से जुड़ा हुआ है। किसी देश का आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जीवन स्तर में सुधार तथा रोजगार में विकास का संकेतक है। आर्थिक विकास की प्रगति एवं बढ़ते हुए औद्योगीकरण के कारण तीव्र पैमाने पर नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। वृहद पैमाने पर औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाओं के साथ कुछ क्षेत्रों का नगरीकृत केन्द्र के रुप में अभ्युदय हुआ है। इन क्षेत्रों में अधिक रोजगार सम्भावनाए सृजित हुई है, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरीकृत केन्द्रों में स्थानान्तरण हुआ। पुणे से सटा हुआ पिम्परी चिंचवाड़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव इत्यादि गावों से रुपान्तरित शहरीक्षेत्र के प्रतिनिधि शहर माने जा सकते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विकास शहरीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है। बढ़ता हुआ औद्योगीकरण नगरीकरण के साथ आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है। आर्थिक विकास स्तर में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर में वृद्धि करता है, जिसका परिणाम व्रस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होता है तथा बढ़ी हुई मांग बड़े पैमाने के उत्पादन व्यवस्था को जन्म देती है। ये सभी कारक शहरीकरण की गति को बढ़ाने में सहायक है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय एवं शहरीकरण की गति में उच्च सह सम्बन्ध है। आर्थिक विकास शहरों एवं कस्बों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार शहरों एवं कस्बों की वृद्धि से कुल जनसंख्या वृद्धि की तुलना में शहरी जनसंख्या में अधिक वृद्धि वृद्धि होती है।

शहरीकरण से उत्पन्न समस्याये एवं उनका समाधान :–

यद्यपि तीव्र गति से शहरीकरण 21वीं शताब्दी की विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। तीव्र शहरीकरण आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है, जिससे औद्योगीकरण एवं व्यापारिक गतिविधियाँ त्वरित हो जाती है तथा आर्थिक क्रियाओं का विविधीकरण हो जाता है, लेकिन अनियोजित एवं विषमतापूर्ण शहरीकरण ने भारत में अनक समस्याओं को जन्म दिया है।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या :–

शहरीकरण से प्रदूषण की समस्या पैदा हो गयी है और यह समस्या दिनो दिन गम्भीर होती जा रही है। अनियोजित एवं बेतरतीब औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्रों के विस्तार से प्रदूषण की समस्या निरन्तर जटिल होती गयी है। औद्योगिक केन्द्रों पर मशीनों तथा वाहनों की शोर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन सर्वाधिक चिन्तनीय स्थिति वायु प्रदूषण की है। नवम्बर 2017 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में वायु प्रदूषण के अत्यधिक बढ़ जाने के फलस्वरुप स्कूलों में छुट्टी करना पड़ा तथा अन्य कई प्रकार के तात्कालिक प्रतिबन्ध लागू करने पड़े। वायु प्रदूषण से विभिन्न प्रकार बिमारिया जन्म ले रही है।

शहरी कचरे के कारण नदियों एवं जलाशयों का जल दूषित होता जा रहा है। कचरे एवं औद्योगिक मलबे के एक जगह पड़े रहने के कारण भूमिगत जल पर भी प्रभाव पड़ रहा है। स्वच्छ पेय जल आपूर्ति की समस्या जटिल होतीन जा रही है। नगरों पे बढ़ते आवासीय विस्तासर के कारण खुले

मैदान एवं क्रीडा स्थल समाप्त होते जा रहे है। शहरों की स्थिति यह होती जा रही है, कि न तो सास लेने के लिए शुद्ध वायु है न पीने के लिए शुद्ध पानी।

आवासीय समस्याए :–

शहरीकरण से आवास की समस्या भी बढ़ी है। छोटे आवासीय इकाइयों निवासियें को धूप एवं रोशनी जैसी नैसर्गिक उपहारों से वंचित रहना पड़ता है। मलीन बस्तियों में रहने वाले लोगों के नारकीय जीवन की स्थिति से समाज एवं सरकार को शर्मिन्दगी झेलनी पड़ती है। बड़े–बड़े महानगरों में जहां एक ओर बहुमंजिली भव्य इमारते है। वहीं पर दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ियाँ है। शहरी क्षेत्र के निकटवर्ती कृति योग्य भूमि आवासीय स्थलों में परिवर्तित होती जा रही है। जलमग्न क्षेत्रों में आवासीय बस्तियों के निर्माण से प्राकृतिक जल निकास के रास्ते निरन्तर अवरुद्ध होते जा रहे है। फलस्वरुप वर्षा के दिनों में अति जल प्लावन (बाढ़) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बारिश के दिनों में मुम्बई का जनजीवन कई बार ठप्प हो जाता है।

जलवायु दशाओं में परिवर्तन :–

औद्योगिक इकाइयों एवं वाहनों के द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन से बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के रासायनिक कण वायुमण्डल में समाहित होते है जिसके कारण न केवल ऋतुओ की दशाओं में परिवर्तन हो रहा है बल्कि अम्लीय वर्षा की समस्या हो गयी है। अम्लीय वर्षा न केवल मानव जीवन के लिए हानिकारक है अपितु अन्य जीव जन्तु एवं वनस्पतियों को भारी क्षति पंहुचा रही है।

नैतिक समस्या :–

बढ़ेते शहरीकरण के कारण चकाचौध एवं आडम्बरपूर्ण आधुनिक जीवन शैली नैतिकता पर प्रहार कर रही है। निम्न आय वर्ग के झुग्गी झोपड़ियों में आश्रय लेने वाले लोग उच्च जीवन स्तर आकांक्षा से अनैतिक कार्य करने लगते है तथा चोरी, डकैती, अपराध वैश्यावृत्ति तस्करी आदि। कारण यह है कि अब नगरीय बेरोजगारी की मात्रा को घटाने में असमर्थ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई अतिरेक श्रम शक्ति को देखते हुए नगरों में रोगजार सृजन की सम्भावनाए कम हो रही है। अतः भारत में प्राप्त शहरीकरण की तुलना में शहरी केन्द्रों की समाहित सामर्थ्य बहुत कम है।

उपुर्यक्त समस्याओं के निराकरण में प्रभावी सिद्ध हो सकते है।

(1) प्रदूषण उत्पन्न करने वाले औद्योगिक इकाइयों एवं वाहनों की पहचान कर सक्षम प्राधिकरणों को सुधारात्मक उपाय लागू कराने में तत्परतापूर्वक कार्य करना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल के आदेशों को लागू करने में सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकारों को सहयोग करना चाहिए स्वच्छ भारत अभियान को राजनैतिक कार्यक्रम के स्थान पर सामाजिक आन्दोलन का स्वरुप दिया जाना आवश्यक है।

(2) भविष्य में नियोजित शहरी विकास का प्रयास किया जाना यथेष्ट है। सेटलाइट सिटी की अवधारणा को मूर्तरुप दिया जाना एक कारगर उपाय हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षे. के तर्ज पर अन्य शहरी क्षेत्रो के उपनगरीय क्षेत्रों का कारगर प्रबन्धन भविष्य के लिए तरक्की के नये मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

(3) ग्रामीण अधोसंरचना का विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना चाहिए, ताकि शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति हतोत्साहित हो।

(4) मलीन बस्तियों के निवासियों के लिए निःशुल्क शहरी अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय है। मलीन बस्तियों के स्थान पर आवासीय संकुल का निर्माण सरकार द्वारा करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

(5) नदियों एवं जलाशयों का प्रदूषण समाप्त करने के लिए पर्याप्त सीवरेज प्रणाली का विकास प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। नगरों के कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था में सुधार कर कूड़ा डम्पिंग स्थलों पर कूड़ा से बिजली बनाने का संयंत्र लगाना कारगर हो सकता है।

आर्थिक विकास के साथ शहरीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सरकार एवं समाज के सक्रिय सहयोग से शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान संभव भी है।

सन्दर्भ :–

सिन्हा वी0सी0 – आर्थिक पर्यावरण, एस0 बी0 पी0 डी0 आगरा।
मिश्र जगदीश नारायण – भारतीय अर्थव्यवस्था, किताब महल, इलाहाबाद।
मिश्र एस0के0 एवं पुरी वी0के0 – हिमालया पब्लिंसिग हाउस, दिल्ली।
सिंह एस0के0 – आर्थिक पर्यावरण, साहित्य भवन पब्लिकेशनस आगरा।
अग्रवाल ए0एन0 – भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व प्रकाशन, दिल्ली।
दत्त एवं सुन्दरम – भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली।
ममोरिया चतुर्भुज – भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिशर्स एंव डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा।
गौतम अलका – संसाधन एं पर्यावरण शारदा पुस्तक भवन आगरा।
मिश्र जे0 पी0 – भारतीय अर्थव्यवस्था विजडम बुकस वाराणसी।
सिंह बी0 के0 – भारतीय अर्थव्यवस्था कुशल पब्लिकेशनस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स वाराणसी।
भारत की जनगणना –2011